कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू—प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश क्रमांक / एफ—5 / 919 / 2019 / 10—11 / 6 हिने भोपाल, दिनांक 18 / 02 / 2020 प्रति.

वनमण्डलाधिकारी, (सामान्य) वन मंडल, दक्षिण बाालाघाट, मध्यप्रदेश।

विषय:— बालाघाट जिले के अन्तर्गत ग्राम खैरलांजी में शासकीय हाई स्कूल के भवन निर्माण हेतु 0.410 हेक्टेयर वन भूमि जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भः— मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट का पत्र क्रमांक/मा०चि०/2019/1577 दि० 30.11.2019.

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रस्ताव अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट एवं आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत सरकार द्वारा जारी नवीन गाइड लाईन, 2019 अनुसार 01 हेक्टेयर तक वन भूमि में प्रत्यावर्तन के अधिकार राज्य शासन को प्रदत्त है। राज्य शासन की ओर से उपरोक्त प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :--

- 1- Legal status of the forest land shall remain unchanged.
- 2- इस प्रकरण में ऊर्जावन रोपण कार्य के तहत 260 पौधे रोपित किये गए थे, उक्त वृक्ष काटे जावेंगे। अतः प्रकरण में 520 पौधों की रोपण योजना तैयार कर उसकी राशि आवेदक संस्थान से प्राप्त करने हेतु मांगपत्र जारी करें एवं ऑनलाईन राशि जमा करावें।
- 3- NPV: a) Net Present Value(NPV) for the 0.410 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.
- 4- b) Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.

- 5- User agency shall restrict the felling of saplings upto 260 number in the diverted forest land.
- 6- All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).
- 7- The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector. This certificate should be uploaded on portal with compliance report.
- 8- User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
- 9- The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
- 10- No labour camp shall be established on the forest land.
- 11- The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
- 12- The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
- 13- Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018.
- 14- Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
- 15- The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).

उपरोक्तानुसार एन.पी.व्ही. की राशि तथा 520 पौधों के रोपण योजना की राशि ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा करावे। तत्पश्चात स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन आवेदक संस्थान से कराकर पालन प्रतिवेदन वेब पोर्टल पर अपलोड कराने के उपरांत इस कार्यालय को भिजवाये। जब तक इस कार्यालय द्वारा औपचारिक स्वीकृति जारी नहीं की जाती है तब तक आवेदक संस्थान को कार्य करने / क्षेत्र हस्तांतरण की अनुमति जारी न की जावे।

(सुनील अग्रवाल)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध) मध्य प्रदेश, भोपाल पृ. क्रमांक / एफ-5 / 919 / 2019 / 10-11 / 688 भोपाल, दिनांक 18 02 | 2020 प्रतिलिपि:-

- 1. मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त बालाघाट, मध्यप्रदेश।
- 2. जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, पोस्ट—खैरलांजी, तहसील—कटंगी, बालाघाट, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध) मध्य प्रदेश, भोपाल